उपेक्षा | कच्चा रास्ता बना मुसीबत, कीचड़ और गड्ढों से गुजरने मजबूर ग्रामीण

78 साल बाद भी पक्की सड़क को मोहताज बसनिया गांव



डिंडौरी/अमरपुर, नवभारत 8 अक्टूबर। सरकारें बदलती रहीं, विकास के दावे होते रहे, लेकिन विकासखंड अमरपुर की ग्राम पंचायत खरगहना के आश्रित ग्राम बसनिया तक आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है।

आजादी के 78 साल बाद भी ग्रामीण कच्चे, पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से आवागमन करने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में सड़क की स्थिति और बदतर हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों के बीच ग्रामीणों का सफर किसी चुनौती से कम नहीं है।मोहनझिर-भानपुर मुख्य मार्ग से भगवान वारा तक करीब दो किलोमीटर लंबा रास्ता आज भी पक्की सड़क की बाट जोह रहा है।

मिट्टी-मुरूम डालकर रास्ते को करते हैं दुरुस्त

ग्रामीणों के मुताबिक, ग्राम पंचायत द्वारा हर साल मिट्टी-मुरूम डालकर रास्ते को दुरुस्त करने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन बारिश होते ही सड़क फिर गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो जाती है। सड़क की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोपहिया वाहन चालकों को भी यहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों के इलाज तक संकट

सड़क की बदहाली का सबसे ज्यादा खामियाजा स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के दौरान कीचड़ भरे रास्ते पर बच्चे फिसलते और गिरते हुए स्कूल पहुंचते हैं। इस दौरान उनकी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म तक खराब हो जाती हैं। वहीं, गांव में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर एंबुलेंस का पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

आवेदन दिए, आश्वासन मिले, लेकिन सड़क नहीं बनी

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंत्री, विधायक, जनपद पंचायत और कलेक्टर की जनसुनवाई तक में कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं। हर बार प्रस्ताव भेजने और आगामी बजट में सड़क निर्माण कराने का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आया।



बाईकों की आमने-सामने भिड़त, 2 की मौत

जरहा और कौड़िया के बीच हादसा

नौरोजाबाद नवभारत 8 अक्टूबर। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत जरहा चौराहा के आगे कौड़िया पुल के पास दो बाईकों की आमने सामने भिंडत हो गईं। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही दो युवकों की मौत हो गईं।

जानकारी के अनुसार कि अमृतलाल बैगा, कैलाश बैगा एवं सागर उमरिया की ओर से घुल घुली की ओर पल्सर गाड़ी क्रमांक एमपी 54 जेड बी 3918 से आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घुल घुली की ओर से मंगल कोल अपने नाती शंकर कोल के साथ बाईक क्रमांक एमपी 54 एम 1263 से ग्राम भुंन्डी जा रहे थे तभी अचानक कौड़िया पुल के समीप जोरदार दोनों बाइकों में आमने-सामने टक्कर हो गईं।

दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया

दोनों बाईको के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक युवक सहित घायल सागर बैगा पल्सर बाईक मे सवार थे। हादसे मे घायल सागर को 112 की मदद से उपचार के लिए उमरिया चिकित्सालय ले जाया गया। घटना में दूसरी बाइक में सवार घायल मंगल कोल अपने नाती को निजी वाहन से उमरिया इलाज के लिए ले गया।

रामकमल पयासी को मिला वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने 50 हजार का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

मानपुर नवभारत 8 अक्टूबर। नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक 5 निवासी एवं दक्षिण शहडोल वनमंडल में वनरक्षक (डॉग हैंडलर) के पद पर पदस्थ रामकमल पयासी को वर्ष 26 के वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 7 अक्टूबर को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर में आयोजित चीता रिलीज कार्यक्रम के मंच पर प्रदान किया गया।



कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री पयासी को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 50 हजार रुपये का चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

वन्यजीव शिकार की रोकथाम में दिया योगदान-प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री पयासी ने अपने व्यावसायिक कौशल का प्रभावी उपयोग करते हुए वन्यजीव रेस्क्यू तथा शिकार की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनके कार्यों से प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिली। रामकमल पयासी की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ-साथ मानपुर क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है। बेटे की उपलब्धि पर परिवारजनों, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी है।

भूमाफिया के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

वन तालाब को मिला न्याय, कलेक्टर ने जारी किया अवैध निर्माण हटाने का आदेश

मानपुर नवभारत 8 अक्टबर। सार्वजनिक संपत्ति को निजी जागीर समझने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। कलेक्टर राखी सहाय एवं अनुविभागीय अधिकारी मानपुर हरनीत कौर कलसी की संयुक्त पहल पर मानपुर के सबसे पुराने सार्वजनिक तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया।

न्यायालय कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा पारित आदेश पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जाता है कि तालाब के जांच में खुलासा हुआ था कि खसरा नंबर 716, 717, 718 रकबा 2.810 हेक्टेयर की भूमि, जो 1953-54 से राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निस्तार के तालाब के रूप में दर्ज है, उसे कूटरचित तरीके से 2011-12 में बंटवारा पंजी क्र. 135 के माध्यम से निजी नाम पर कर लिया गया।

2400 वर्गफीट में 5 फीट ऊंचा पक्का निर्माण किया गया-जांच में पाया गया कि अनावेदक कमलेश गुप्ता द्वारा तालाब की भराई कर उस पर 2400 वर्गफीट में 5 फीट ऊंचा पक्का निर्माण और 11 विशाल पक्के पिलर खड़े कर दिए गए थे, ताकि भविष्य में पूरे तालाब की जमीन पर कब्जा किया जा सके। एसडीएम मानपुर द्वारा 31.08.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में इस पूरे खेल को अवैध और पर्यावरण के खिलाफ माना गया।

कलेक्टर का सख्त और सराहनीय आदेश-मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर राशि सहाय ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेशित किया है कि अनावेदक 15 दिवस के भीतर स्वयं के व्यय से समस्त अवैध निर्माण हटाए। यदि 15 दिन में नहीं हटाया तो एसडीएम मानपुर पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर निर्माण को ध्वस्त करेंगे, और ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च अतिक्रमणकर्ता से भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा।



करंजिया के छात्रों को मिला शान पुरस्कार

करंजिया, नवभारत 8 अक्टूबर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के 6 छात्रों ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले का मान बढ़ाया है। प्राचार्य केशव प्रसाद तिवारी एवं माध्यमिक शिक्षिका राजश्री शुक्ला के नेतृत्व में 5 अक्टूबर को दल भोपाल के लिए रवाना हुआ। दल में करंजिया से 1, डिंडौरी से 3 और शहपुरा से 2 कुल 6 बच्चे और 2 शिक्षक शामिल थे। अगले दिन सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर बच्चों द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। जबलपुर संभाग की ओर से लगाई गई इस मनमोहक प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। डिंडौरी जिले के बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को राज्य स्तर पर सराहा गया और शान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

त्यौहारों में शांति भंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

थाना परिसर में आयोजित बैठक में समितियों को दिए सुरक्षा के निर्देश

शहपुरा नवभारत 8 अक्टूबर। आगामी नवरात्रि, दीपावली सहित अन्य त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शहपुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम शहपुरा फरहान इरफान जमादार ने की।

बैठक में प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने आयोजन समितियों और नागरिकों के साथ त्यौहारों के दौरान कानून-व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में आगामी धार्मिक आयोजनों, जुलूस एवं चल समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा साफ-सफाई और बिजली व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।



जारी निर्देशों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएं-एसडीएम ने आयोजन समितियों से कहा कि सभी धार्मिक कार्यक्रम निर्धारित नियमों एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाएं, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि त्यौहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क रहेगी। थाना प्रभारी अनुराग जामदार ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें और संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। अधिकारियों ने आयोजन समितियों से भीड़ प्रबंधन, बिजली एवं अन्य आवश्यक इंतजामों को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा।

सभी त्यौहार भाईचारे व सद्भाव के साथ मनाए : कलेक्टर



डिंडौरी। कलेक्टर की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 11 से 20 अक्टूबर तक नवरात्र, दशहरा एवं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्यौहारों के दौरान साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा विसर्जन स्थलों पर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जाने वाले मार्गों का पूर्व से निरीक्षण कर मार्ग में आने वाले पेड़ों की आवश्यक छटाई तथा विद्युत तारों एवं कनेक्शनों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

समय पर नहीं हो रहा कर्मचारियों का वेतन भुगतान

ट्रेजरी कार्यालय में हफ्तों अटके रहते हैं वेतन के देयक, कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी

उमरिया नवभारत 8 अक्टूबर। शासकीय कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने शासन स्तर से स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद जिले में वेतन भुगतान प्रक्रिया में देरी के आरोप सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन के देयक ट्रेजरी कार्यालय पहुंचने के बाद भी कई-कई दिनों तक लंबित रखे जाते हैं, जिसके कारण समय पर वेतन उनके खातों में नहीं पहुंच पाता।

कर्मचारियों के अनुसार, विभागों द्वारा वेतन संबंधी देयक समय पर तैयार कर ट्रेजरी कार्यालय भेजे जाते हैं, लेकिन वहां प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होने से भुगतान प्रभावित होता है। आरोप है कि कई देयकों को सप्ताहों तक रोककर रखा जाता है और उन्हें आगे बढ़ाने में बेवजह समय लगाया जाता है।

आखिर क्यों रोके जाते हैं देयक?-कर्मचारियों का कहना है कि यदि किसी देयक में वास्तविक तकनीकी या दस्तावेजी कमी है तो संबंधित विभाग को तत्काल इसकी जानकारी देकर कमी दूर कराई जानी चाहिए। लेकिन बिना स्पष्ट कारण देयकों को लंबे समय तक लंबित रखना कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को बैंक की किस्त, बच्चों की फीस, घरेलू खर्च सहित अन्य आर्थिक दायित्वों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जिम्मेदारी तय करने की उठी मांग-कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि वेतन देयकों के लंबित रहने की स्थिति की समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर देयक लंबित रखने की समय-सीमा और जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से वेतन संबंधी देयक कई दिनों तक लंबित रहते हैं।

वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग-अब सवाल यह है कि जब विभागों से वेतन देयक समय पर भेजे जा रहे हैं, तो ट्रेजरी स्तर पर इनके भुगतान में देरी क्यों हो रही है? इस मामले में प्रशासन द्वारा जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।

पटवारी और तहसील स्तर से नहीं मिल रहा स्पष्ट समाधान, किसान परेशान

एग्रीस्टैक की तकनीकी अड़चन से धान पंजीयन अटका

नवभारत चिल्हारी 8 अक्टूबर। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक की तकनीकी समस्या के चलते अटक गया है। किसानों का कहना है कि गिरदावरी की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद एग्रीस्टैक में भूमि संबंधी जानकारी सही तरीके से अपडेट या प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके कारण पात्र किसानों का पंजीयन आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

एग्रीस्टैक में भूमि की जानकारी नहीं आने या त्रुटि प्रदर्शित होने पर किसान पटवारी और तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें समस्या के निराकरण को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है और



अलग-अलग स्तर से गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। इसके चलते किसान बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

समय पर भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी कराई

किसानों का कहना है कि उन्होंने समय पर अपनी भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी कराई है। इसके बावजूद यदि एग्रीस्टैक की तकनीकी समस्या के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहा है तो इसका नुकसान किसानों को नहीं उठाना चाहिए।

अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

पंजीयन की अंतिम तिथि नजदीक आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि एग्रीस्टैक की तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए, संबंधित अधिकारियों को किसानों की भूमि संबंधी त्रुटियों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए जाएं और जिन किसानों का पंजीयन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है, उनके लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।

त्यौहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील

एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित

मानपुर नवभारत 8 अक्टूबर। आगामी त्यौहारों नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुविभागीय अधिकारी हरनीत कौर कलसी की अध्यक्षता में नपा मानपुर के सभाकक्ष में गुरुवार को सुबह 11 बजे उपखण्ड स्तरीय शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तहसीलदार मानपुर अभ्यानंद शर्मा, मुख्य नपाधिकारी रचियता अवस्थी,थाना प्रभारी गर्ग, सामाजिक संगठन, व्यापारी, विद्युत व स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थिति रहा। बैठक में भाजपा



जिला महामंत्री हरीश विश्वकर्मा, रसिक खंडेलवाल किसान मोर्चा जिला महामंत्री, विद्युत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित नगर के समस्त जनप्रतिनिधि, पत्रकार राजू गुप्ता, अजय पयासी, रामाविलाश त्रिपाठी, जय प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे।

असामाजिक तत्वों की होगी सख्त निगरानी-बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्यौहारों के दौरान साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, यातायात, डीजे एवं लाउडस्पीकर के न्यायालय के नियमानुसार उपयोग, तथा असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। एसडीएम हरनीत कौर कलसी ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार साथियों से अपील की कि प्रशासन का सहयोग कर त्यौहारों को आपसी भाईचारे के साथ सभी मिलकर मनाएं।

लंबित स्वत्वों के 10 प्रकरणों का किया निराकरण

जनजातीय कार्य विभाग की सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लिए पहल

डिंडौरी, नवभारत 8 अक्टूबर। कलेक्टर के निर्देशानुसार जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत एवं सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित स्वत्वों के त्वरित निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि किसी भी सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, डीपीएफ, एनपीएस, अवकाश नगदीकरण सहित अन्य देय स्वत्वों के भुगतान के लिए जनसुनवाई में आने की आवश्यकता नहीं पड़े। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर सेवा निवृत्ति की तिथि पर पात्रतानुसार समस्त स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित करें। निर्देशों के पालन में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लंबित स्वत्वों के 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इनमें उपादान का 01 तथा समूह बीमा योजना के 09 प्रकरण शामिल हैं। विकासखण्ड डिण्डौरी के सेवा निवृत्त सहायक शिक्षक रघुवीर सिंह तेकाम को उपादान का लाभ प्रदान किया गया। 5 अन्य कर्मचारियों को समूह बीमा योजना का लाभ प्रदान किया गया है।

मांग | एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, फसल गिरदावारी, खसरा एंट्री और पट्टे की मांग

50 सालों से जोता-बोया, फिर भी कागजों में बेगाने



नवभारत चिल्हारी 8 अक्टूबर। क्षेत्र के सैकड़ों भूमिहीन कब्जेधारी किसानों का दर्द आखिरकार सडक़ों पर छलक ही पड़ा। पिछले 50 वर्षों से कड़ा परिश्रम कर मेढ़-मिट्टी बांधकर खेती कर रहे और अपने परिवारों का पेट पाल रहे गरीबों के सब्र का बांध अब टूट चुका है।

भूमिहीन कब्जेधारी कृषक संगठन के बैनर तले किसानों ने मानपुर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शासन-प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि यदि 7 दिवस के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन व प्रशासन की होगी।

वर्ष 2005 के बाद खसरे से गायब हुए किसान

ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने आरोप लगाया कि वे दशकों से शासन की भूमि पर काबिज होकर खेती-किसानी कर रहे हैं और वहीं छोटे-छोटे मकान बनाकर रह रहे हैं। लेकिन वर्ष 2005 के बाद से अचानक राजस्व अभिलेखों (खसरा) में उनके कब्जे दर्ज करना बंद कर दिए गए। नतीजतन, असली पसीना बहाने वाले इन किसानों को न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही उनकी फसलों का कहीं पंजीयन हो पा रहा है।

सरकारी योजनाओं से बेदखल

किसानों ने एसडीएम के समक्ष अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि जमीन के कागजी अधिकार नहीं होने की वजह से वे केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से पूरी तरह वंचित हैं। न तो किसानों को किसान सम्मान निधि मिल पा रही है और न ही फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर आईडी या सरकारी खाद-बीज का लाभ मिल रहा है।

निरस्त पट्टों की जांच कराकर बहाली की मांग

किसानों ने ज्ञापन में एक और गंभीर मुद्दा उठाया कि पूर्व में जिन वास्तविक भूमिहीन गरीबों को शासन द्वारा पुनर्वास व व्यवस्थापन के तहत पट्टे जारी किए गए थे, उनमें से कई पट्टों को बिना उचित कारणों के निरस्त कर दिया गया है। किसानों ने मांग की है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर मौके का मुआयना कराया जाए और पात्र गरीबों के निरस्त पट्टे तत्काल बहाल किए जाएं।

किसानों के नाम पर आईं मशीनें हो गईं गायब

ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल का हिसाब कौन देगा



नवभारत चिल्हारी 8 अक्टूबर। किसानों को आधुनिक खेती की सुविधा देने सहकारी समितियों में उपलब्ध कराए गए 60 एचपी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल सहित अन्य कृषि उपकरणों की स्थिति अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कहीं मशीनें लंबे समय से खड़ी-खड़ी जंग खा रही हैं तो कई स्थानों पर कृषि उपकरणों के गायब होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। जिस मशीनरी को किसानों को घंटे के हिसाब से उपलब्ध कराकर खेती आसान बनानी थी, उसका बड़ा हिस्सा आज उपयोग के बजाय धूल और जंग खा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसानों के नाम पर आई इस मशीनरी की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी?

मशीनों का पूरा हिसाब कहां है-यदि किसी समिति से ट्रैक्टर या कृषि उपकरण गायब हुए हैं, तो उनकी खरीद, सुपुर्दगी, स्टॉक रजिस्टर, संचालन, मरम्मत, बीमा और पुलिस रिपोर्ट का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। आखिर सरकारी/सहकारी संपत्ति समिति परिसर से गायब हुई तो इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को कब मिली? वहीं दूसरी ओर, जो मशीनें मौजूद हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय होना जरूरी है।

मशीनें किसानों तक क्यों नहीं पहुंचीं?-किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की योजना का मकसद तभी पूरा होगा, जब उपकरण वास्तव में खेतों तक पहुंचें। इसलिए जिले की सभी संबंधित समितियों में मशीनरी का भौतिक सत्यापन, खरीद की तारीख और कीमत क्या थी? कितने ट्रैक्टर वर्तमान में उपलब्ध हैं? और कितनी मशीनरी चोरी या गायब होने की रिपोर्ट है।